Ministry of Water Resources has launched a State Sector Scheme for Repair, Renovation and Restoration (RRR) of water bodies which has multiple objectives like comprehensive improvement and restoration of water bodies thereby increasing tank storage capacity, groundwater recharge, increased availability of drinking water etc.

The House then adjourned for lunch at one minute past one of the clock.

The House reassembled after lunch at two of the clock,
MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair.*

STATEMENTS BY MINISTERS — *Contd.*

Kokrajhar militant attack on the 5th August, 2016

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, statement by hon. Home Minister, Shri Raj Nath Singh.

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह): महोदय, असम के कोकराझार जिले में 5 अगस्त, 2016 को बालाजन तिनाली में एक भीड़-भाड़ वाले साप्ताहिक बाजार में उग्रवादी हमला हुआ। उपलब्ध सूचना के अनुसार, प्रातः लगभग 11.30 बजे सेना की वर्दी में उग्रवादियों ने कथित रूप से कुछ मकानों और दुकानों में आग लगा दी, जिससे एक सिलेण्डर फट गया तथा उस क्षेत्र में आग फैल गई। इसके बाद उन उग्रवादियों ने दुकानदारों की भीड़ पर अंधाधुंध गोलीबारी की। इस हमले में 15 निर्दोष लोगों जिनमें 8 बोडो, एक महिला, एक बालक और चार अन्य लोग शामिल हैं, की जानें गईं। 19 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए, जिनका जिले तथा राज्य की राजधानी के विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। हमले के बाद राज्य पुलिस और सुरक्षा बलों ने तुरन्त जवाबी कार्यवाही की तथा एक उग्रवादी को मार गिराया, जिसकी अभी शिनाख्त की जानी है। मारे गए उग्रवादी से एक ए.के. 56 रायफल, लाइव गोला बारूद की दो मैगजीन और एक हथगोला बरामद किया गया। इस हमले में शामिल उग्रवादियों की वास्तविक संख्या और उग्रवादी संगठन की जांच की जा रही है।

राज्य सरकार ने इस हमले में घायल हुए लोगों के उपचार की संतोषजनक व्यवस्था की है। हमले में मारे गए लोगों के निकट संबंधियों को 5 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायल लोगों को 1 लाख रुपए और मामूली रूप से घायल लोगों को 20,000 रुपए की अनुग्रह राहत प्रदान की गई है। इस उग्रवादी हमले की जांच करने के लिए कोकराझार पुलिस थाने में एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। मैं अपने प्राण गंवाने वाले निर्दोष लोगों पर हुए इस कायरतापूर्ण हमले की कड़ी निदा करता हूं तथा इस सम्मानित सदन की ओर से शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं उन्हें दुख की इस कठिन घड़ी में शक्ति प्रदान करे। सभी सदस्यों की ओर से, मैं घायल हुए लोगों के पूरी तरह शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना करता हूं।

मैंने असम सरकार तथा राज्य में सुरक्षा बलों से इस हमले में शामिल उग्रवादियों को पकड़ने और मानवता के विरुद्ध इस अपराध के लिए उन्हें उचित दंड दिलाने के लिए स्पष्ट रूप से कहा है।

SHRI RIPUN BORA (Assam): Sir, I want to seek a few clarifications from the hon. Home Minister as it is an incident, which is... ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, yes. Please seek.

SHRI RIPUN BORA: Sir, the first thing, to which I would like to draw the kind attention of the hon. Home Minister is that this entire area, the incident area and the BTAD area, comprising of four Districts, has been an extremist-prone area for the last twenty years, and, considering this aspect, our earlier State Government deployed three companies of CRPF and other security forces. But what has happened is that just after the elections, when the new Government took office, immediately those security forces were withdrawn from that area. It is one aspect.

Now, I come to what happened afterwards. There is very strong Central Intelligence input that these types of incidents may take place before 15th of August. In spite of that information, the State Government is taking the matter very lightly. They did not deploy... ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Put your question.

SHRI RIPUN BORA: One minute, Sir. That area is a very, very sensitive area. The State Government has failed to anticipate the security vulnerability... ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Put your question.

SHRI RIPUN BORA: And, they did not deploy there the security forces that day. My question is: When nearly 4,000 people gathered there, why was this lapse there on the part of the State Government? My third question is this. There is now a controversy on the identity of the extremist who was killed in the encounter by the Army. The police and the intelligence declared his name as Manjay Boro. But when the police called his parents to identify the dead body, the parents denied it saying that this was not of their son. So, this controversy has also created a mystery.

My last question to the hon. Home Minister is this. Immediately after the incident, the National Intelligence Agency people went there the next day. We also went there and met them. But now there is a doubt, according to the information which we have got, that the State Government is not favouring the inquiry by NIA. So, my demand is that the inquiry should be conducted by NIA.

On these four points, I want the clarifications from the hon. Home Minister.

श्री सन्तियुस कुजूर (असम): सर, यह जो घटना हुई है, यह कोई नई घटना नहीं है। वर्ष 2014 में Songbijit group ने ऐसी ही एक घटना को अंजाम दिया था, जिसमें मुस्लिमों की हत्या

[श्री सन्तियुस कुजूर]

कर दी गई थी। फिर दिसम्बर, 2014 में इसी Songbijit group ने आदिवासियों के ऊपर हमला कर 76 आदिवासियों को मारा डाला था। सर, BTG एरिया और out of BTG एरिया, सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे इल्लीगल आर्म्स बहुत है। इन इल्लीगल आर्म्स को सीज़ करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए है, यह मैं जानना चाहता हूँ।

श्री बिश्वजीत दैमारी (असम): सर, असम का जो बोडोलैंड एरिया है, वहां पर असम के सारे उग्रवादी संगठनों का stronghold है, जिसके कारण वहां हर समय time-to-time सेंट्रल फोर्सेज़ deploy की जाती है। जब उग्रवादियों की गतिविधियां कम नज़र आती है, तो उस सेंट्रल फोर्स को वहां से हटा लिया जाता है। कभी-कभी इलेक्शंस के नाम पर भी वहां से इन फोर्सेज़ को हटाना पड़ता है। इसलिए मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि वहां की सिचुएशन को देखते हुए हमारी होम मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ जगहों को आइडेंटिफाई करके क्या वहां पर सेंट्रल फोर्सेज़ के कुछ परमानेंट कैम्प्स बनाए जा सकते है, जिसको पूरे देश में होने वाले इलेक्शंस के नाम पर हटाना न पड़े? इन कैम्प्स को ऐसी जगहों पर रखा जाए, जहां से जरूरत पड़ने पर फोर्सेज़ मूव भी कर सकें। ...**(समय की घंटी)**... सर, दूसरी बात यह है कि वहां पर बाकी सारे extremist groups ceasefire में है। उनकी संख्या थोड़ी सी है, लेकिन उनका अपना एक नेटवर्क है। इस सिचुएशन में वे सरकार को उन लोगों को आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकते है, जो ऐसे काम को करते है।

प्रो. राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश): श्रीमन्, कोकराझार में यह बहुत ही दुखद घटना हुई है। दुर्भाग्य से देश के कई हिस्सों में इस तरह की उग्रवादी गतिविधियां लगातार होती रहती है। मैं माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध भी करना चाहूँगा और यह जानना भी चाहूँगा कि जब पूर्वोत्तर से लेकर नेपाल के बॉर्डर और उधर पश्चिम तक तथा छत्तीसगढ़ से लेकर झारखंड तक हर जगह ये गतिविधियां है, तो क्या सीआरपीएफ के फोर्स को और ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है? उस बल की रिक्रूटमेंट ज्यादा करें और उस बल को बढ़ाएँ, क्योंकि जिस तेजी से ये घटनाएँ बढ़ी है, उसे देखते हुए सीआरपीएफ की और ज्यादा बटालियंस खड़ी करने की जरूरत है, इसको सब महसूस करते होंगे। दूसरा, खास तौर से नॉर्थ-ईस्ट का इलाका काफी सेंसिटिव है। बोडोलैंड के आस-पास पहले से ही ऐसी गतिविधियां रही है। इंटेलिजेंस नेटवर्क को मजबूत करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे है? जब तक इंटेलिजेंस में मैनपॉवर नहीं होगी, उसकी accessibility ज्यादा क्षेत्र में नहीं होगी। उग्रवादियों की गतिविधियों की जानकारी तभी मिल सकती है, जब आपके Intelligence के लोगों की तादाद ज्यादा हो और उनकी reach दूर तक हो। तो Intelligence के नेटवर्क को मज़बूत करने के लिए आप क्या करेंगे और CRPF की आवश्यकता को देखते हुए, उसकी battalions को raise करने के लिए क्या कदम उठाएंगे?

SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY (West Bengal): Sir, we share the agony and anguish of the hon. Members. And we also condemn the brutal attack on innocent people. But this is not the first time that this has happened there. As someone has said, such incident took place in that particular area of Kokrajhar in December, 2014 when more than 70 persons were killed. In that District, Bengali Muslims comprise

twenty-one per cent of the population. It is bordering West Bengal, particularly the Cooch Behar District of West Bengal. During December, 2014, hundreds of villagers had to flee to Cooch Behar District of West Bengal and our hon. Chief Minister, Ms. Mamata Banerjee, had to arrange for their shelter, food, medical treatment, etc. Again, this has happened and one of the Ministers of Assam is on record saying that it was not a planned attack; it was an unplanned attack and that is why the Government did not have any information; and the security forces reached the spot half an hour or one hour after the incident. That is why they could not prevent it. But this is not an isolated incident. Kokrajhar District has been affected by it for long. The so-called Bodo agitation was there. And after the Peace Agreement of 2005, people thought that the situation would improve. Again, this has happened. The clarification that I would like to seek from the hon. Minister is whether it is a case of Intelligence failure. If that be the case, whether the Government of India is advising the State Government to take appropriate steps for improving the Intelligence mechanism to prevent recurrence of such incidents in future in a diligent manner.

श्री रवि प्रकाश वर्मा (उत्तर प्रदेश): सर, बहुत important बात यह है कि वे सारे एरियाज़ जो mineral-rich areas है या natural resources-rich areas है, जहां education का स्तर भी गिरा हुआ है, वहां पर इतनी अच्छी क्वालिटी की बंदूकें कैसे मिल जाती है, यह बड़ा अहम सवाल है। सर, कुछ समय पहले मैंने पंजाब केसरी में पढ़ा था कि ईवन दिल्ली में भी, अगर कोई भी चाहे तो नाजायज़ असलहा मंगा सकता है, वे home delivery कर रहे हैं। सर, गृह मंत्रालय के सामने यह एक बहुत बड़ा सवाल है कि हिन्दुस्तान में नाजायज़ असलहों का इतना बड़ा कारोबार चल कैसे रहा है, इसको आप कैसे संभालेंगे?

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): Sir, the Home Minister keeps making strong statements against terrorism indicating that the country is on permanent vigil on the issue of terrorism. Despite that, such a terror act took place in Assam. I would like to know this from the Home Minister. Was there really an Intelligence failure or a security lapse? Also, how do you maintain coordination between the Central Intelligence agencies and the State Intelligence agencies? After elections, the BJP is in power in Assam. Now we have witnessed this terror attack. I do not know if the situation turns into some kind of a communal conflict. The Home Minister must clarify how the coordination between the Central Intelligence agencies and the State Intelligence agencies is maintained. Was there really a security lapse or an Intelligence failure? You tell this to the Parliament, the House, so that we can all collectively put our heads together to prevent such incidents which keep on happening in different parts of our country.

श्रीमती झरना दास बैद्य (त्रिपुरा): सर, होम मिनिस्टर साहब ने स्ट्रांग स्टेटमेंट दी है, लेकिन

[श्रीमती झरना दास बैद्य]

कोकराझार में जो घटना हुई है, वह बहुत दुखद है। मेरा प्रश्न है कि इतने सारे AK-47, AK-56 आर्म्स मिलिटेंट्स के पास कैसे आ जाते है? जब हमारे स्टेट में भी मिलिटेंसी थी, तब हमने इसको देखा था। कोकराझार में AK-47, AK-56 को यूज़ किया गया है और बहुत सारे लोगों को मारा गया है। इसमें कई बच्चे भी है, इसमें महिलाएं भी है और आम आदमी भी है। इस मिलिटेंसी के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि कैसे इसको बंद किया जाए। पूरे देश में मिलिटेंसी फैल रही है। त्रिपुरा में यह आज भी है। त्रिपुरा में यह बंद नहीं हुई है। त्रिपुरा में आज भी ऐसे मिलिटेंट्स है।

मैं भारत सरकार से मिलिटेंसी को खत्म करने के लिए दरख्वास्त करती हूं। जहां पर घटना हुई है, वहां पर परमानेंट कैम्प होना चाहिए, उस डिक्ट्रिक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को परमानेंट कैम्प देना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को इस बारे में initiative लेना चाहिए, वरना ऐसी घटनाएं पूरे नार्थ-ईस्ट में फैल जाएंगी।

SHRI AHAMED HASSAN (West Bengal): Sir, I want to ask our hon. Home Minister some questions regarding this massacre. I appreciate that he has strongly condemned the incident. I remember that last time, when innocent *Santhal adivasis* were killed, our Home Minister went to the spot and he took strong steps and the problem was tackled immediately. I, personally, congratulate our Home Minister for that.

But, now, I want to ask him. This has been going on in the lower Assam for the last 20-25 years. In 1993-94 also, there was a huge massacre. After that many massacres have taken place.

Secondly, nearly six lakh people fled their homes a few years back and became refugees. It is a human...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Put your question.

SHRI AHAMED HASSAN: Yes, Sir. My first question is this. Hon. Home Minister has not mentioned in the statement, as to which group has done this type of massacre this time. Secondly, from where does these terrorists get these types of sophisticated arms and ammunition? What is the report? Who is providing them money to create this type of chaos in our country? My third question is: As it has been happening at regular intervals, why are you not considering creating a *Gram Raksha Vahini* or Village Defence Force? ...(*Time-Bell rings*)... Just a minute, Sir. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have asked three questions. ...(*Interruptions*)... Three questions will do.

डा. अनिल कुमार साहनी (बिहार): उपसभापति महोदय, कोकराझार में जो उग्रवादी हमला हुआ है, उसमें वहां की सरकार और इंटेलिजेंस फेल हुई है। वहां पर आगे से ऐसा न हो, खास

कर जो उग्रवादी लोग है — हमारे बिहार के लोग भी वहां पर कमाने के लिए जाते है, रोजी, रोजगार के लिए जाते है, उन पर भी हमला किया जाता है। वे लोग भी वहां पर घायल होते है, मारे जाते है। आपने इस घटना में जो लोग मारे गए है, उनको पांच लाख रुपये का मुआवजा दिया है। हमारी मांग है कि इस मुआवजे की राशि में कुछ बढ़ावा किया जाए, ताकि जिनके परिवार के लोग मरे है, उनको राहत मिल सके। मरे हुए लोगों के परिवार के सदस्य को नौकरी देने का भी प्रावधान किया जाए, जिससे उनके परिवार का पालन-पोषण ठीक तरह से हो सके।

SHRI BHUBANESWAR KALITA (Assam): Sir, hon. Home Minister has made a statement, but many questions had been raised on this. There were questions about intelligence failure, removal of security forces, which were on duty there, about two months back and the questions about preparedness of the administration. I will not touch upon these subjects because these have already been mentioned. My limited question is this. Militancy has gone down in Assam and it is in everybody's knowledge that their numbers are going down. They are only a few because they are either on ceasefire or with talks with the Government of India or the State Government. With this reduced trend, how can the militants commit such a huge massacre? The main thing is illegal weapons. My question is: Is the Government going to take any step to reduce and ban illegal weapons in Assam, particularly, in those affected areas? The militants are less in number and their leaders are in other countries, in the neighbouring countries. What step is the Government going to take to bring back those militant leaders who are in the neighbouring countries and put them before the law?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, hon. Home Minister.

श्री राजनाथ सिंहः डिप्टी चेयरमैन सर, North East में पिछले 50-60 वर्षों से लगातार उग्रवादी घटनाएं हो रही है। मैं समझता हूं कि इस सदन के सभी सम्मानित सदस्य इस हकीकत से परिचित होंगे, लेकिन मैं सदन को इस बात की जानकारी देना चाहता हूं कि असम में 1988 के बाद सबसे कम हिंसा यदि हुई है, तो 2015 और 2016 में हुई है।

डिप्टी चेयरमैन सर, हम सब के लिए यह भी संतोष और प्रसन्नता की बात है कि 2015 में security forces का कोई personnel मारा नहीं गया है, कभी हताहत नहीं हुआ है। मैं इसे भी major achievement मानता हूं। पिछले दस वर्षों की तुलना में civil casualties भी बहुत कम हुई है। अभी हाल में असम में विधान सभा चुनाव हुए, वे भी शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न हुए है। इसके पहले भी NDFB(S) ने वहां एक बड़ी वारदात दिसम्बर, 2000 में की थी, जिसमें में लगभग 63 आदिवासी मारे गए थे। जैसा हमारे माननीय सदस्यों ने कहा, उसके बाद हमने उस पर कठोर कार्रवाई की थी। Operation के दौरान उधर से security forces को मारने की जो कोशिश की गई, उसके लिए defence को और security forces को जो कुछ भी कार्रवाई करनी पड़ी, उसमें ऐसे 39 उग्रवादी मारे गए थे और लगभग 600 से अधिक संख्या में इस समय behind the bars किए जा चुके है। असम के बारे में सामान्यतः एक धारणा थी कि अब स्थिति काफी हद तक शांतिपूर्ण हो गई है, लेकिन यह जो घटना हुई है, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सदन को यकीन

[श्री राजनाथ सिंह]

दिलाना चाहता हूं कि चाहे कोई व्यक्ति हो अथवा कोई संगठन हो, हम पूरी ताकत लगाकर यह कोशिश करेंगे कि जो कुछ भी उसने किया है, उसका पूरा खामियाज़ा उसको भुगतना पड़े। हम अपनी तरफ से यह पूरी कोशिश करेंगे।

कुछ सम्मानित सदस्यों ने जो queries की है, मैं उनके बारे में जानकारी देना चाहता हूं। जहां तक security forces के deployment का प्रश्न है, चुनाव के समय Election Commission जितनी फोर्सेज़ की डिमांड करता है, उस डिमांड के आधार पर जितनी हम उसकी डिमांड को पूरा कर सकते है, पूरा करने की कोशिश करते हैं। जब चुनाव सम्पन्न हो जाता है, कुछ फोर्सेज़ स्वाभाविक रूप से पुनः वापस बुला ली जाती है, deployment में कमी हो जाती है, इसमें कोई दो मत नहीं हैं। लेकिन इस समय वहां पर हमारी CRPF की 8 कम्पनियां लगी हुई है, मैं केवल कोकराझार की बात कर रहा हूं कि कोकराझार जिले में 8 कम्पनियां लगी हुई हैं और इस समय आर्मी की भी वहां पर 9 कम्पनियां लगी हुई हैं। आर्मी की 4 एडिशनल कम्पनियों को वहां पर 6 अगस्त को भेजा गया है, मैं यह जानकारी देना चाहता हूं। Bodoland एरिया एक stronghold, पहले रहा हो, यह उग्रवादियों का है, लेकिन उग्रवादियों के खिलाफ जो प्रभावी कार्रवाई हुई थी, उसके परिणामस्वरूप उनके अंदर एक हताशा पैदा हुई थी और ऐसे लगता था कि वे depression में चले गए है। फिर भी वहां पर फोर्स का deployment है। हमारे मित्र राम गोपाल जी ने यह जानना चाहा है कि क्या हम CRPF की स्ट्रेंथ बढ़ाने पर विचार कर रहे है या नहीं कर रहे है? मैं उनको यह जानकारी देना चाहता हूं कि जितनी भी हमारी paramilitary forces है, उनमें जो भी vacancies है, सारी vacancies को जल्दी से जल्दी fill up करने के लिए निर्देश दिए जा चुके है और वह process भी प्रारम्भ हो चुकी है। उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग भी होती है। डिप्टी चेयरमैन सर, जिस प्रकार से refresher courses होते है, उसी प्रकार से refresher training भी paramilitary forces की चलती रहनी चाहिए, यह काम भी हमने प्रारंभ किया है और उसमें और अधिक तेजी लाने की कोशिश करेंगे।

डिप्टी चेयरमैन सर, Intelligence failure की बात की गयी। कहने को कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन हम इसे Intelligence failure नहीं मानते। इस में स्टेट Intelligence agency और सेंट्रल Intelligence agency के बीच coordination रहता है। यह केवल हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान का कोई भी राज्य हो, वहां की स्टेट Intelligence agency और सेंट्रल Intelligence agency बराबर coordination बनाकर काम करती है। हमारे former Home Minister चिदम्बरम साहब यहां बैठे है और मैं समझता हूं कि उनका मुझ से ज्यादा अनुभव है, वे भी अच्छी तरह जानते है कि Intelligence agencies को और अधिक effective बनाने के लिए और साथ ही उन्हें strengthen करने का प्रयास किसी भी गवर्नमेंट में लगातार चलता रहता है। यह आपके समय में भी हुआ है और हम लोग भी इसे और effective बनाने की कोशिश कर रहे है। चरण दास जी ने प्रश्न पूछा है कि उनके पास इतने सारे आर्म्स कैसे आ जाते है? मैं बहुत ज्यादा डिटेल्स में बताने की आवश्यकता महसूस नहीं करता, लेकिन इस हकीकत को नकारा नहीं जा सकता है कि external agencies का भी हाथ है। मैं इस संबंध में सिर्फ इतना ही कहना पर्याप्त समझता हूं।

सर, कई लोगों ने सवाल पूछे है कि कैसे इस प्रकार के असलहे, बंदूकें वहां के उग्रवादियों के हाथों में आ जाती हैं। इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता कि कुछ external agencies

भी इस में काम कर रही है। सर, अहमद हुसैन साहब ने name of the group involved in the incident के बारे में पूछा है। अभी तक जो मोटी-मोटी जानकारी आ रही है और समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुई है, मैं अभी निश्चित तौर पर नहीं कह सकता कि किस insurgent group का इस में हाथ है। उसकी छानबीन हो रही है और पूरे मामले की जांच-पड़ताल वहां की स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। वहां के कोकराझार पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हुई है। डिप्टी चेयरमैन सर, उस की investigation इस समय चल रही है। हम यह देखेंगे कि यदि investigation ठीक तरीके से नहीं हो पा रही है, तो वहां की राज्य सरकार के परामर्श से यदि आवश्यक हुआ, तो हम एनआईए को पूरी-की-पूरी investigation सौंपने को तैयार है। मैं सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं।

सर, मुआवजा बढ़ाने की भी बात कही गयी है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के compensations प्रायः स्टेट गवर्नमेंट ही देती है। यह स्टेट गवर्नमेंट का jurisdiction है और मैं इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन जैसा माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है, मैं एक बार वहां के मुख्य मंत्री से चर्चा जरूर करूंगा।

डिप्टी चेयरमैन सर, मुझे इतना ही कहना है और मैं सदन को पुनः यकीन दिलाना चाहता हूं कि चाहे उग्रवाद की समस्या हो या आतंकवाद की समस्या हो, इनसे जूझने के लिए केवल सरकार ही पर्याप्त नहीं है बल्कि सब के सहयोग से ही हम इस बड़ी चुनौती का सामना कर सकते हैं और इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं।

SHRI BHUBANESWAR KALITA: What about migrant illegal workers?

श्री राजनाथ सिंहः मैंने बोल दिया है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is okay. Now, Shri Jagat Prakash Nadda to move the Mental Health Care Bill, 2013.

GOVERNMENT BILL

The Mental Health Care Bill, 2013

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGAT PRAKASH NADDA): Sir, I move:

> That the Bill to provide for mental health care and services for persons with mental illness and to protect, promote and fulfill the rights of such persons during delivery of mental health care and services and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration.

The question was proposed.

DR. T. SUBBARAMI REDDY (Andhra Pradesh): I am on a point of order.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What is your point of order?